



VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 01 AUG 2023 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2419)

Name of Candidate	NEERAT SONGARA		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	1447625
Center	MN	Date	01/Aug/2023

INDEX TABLE		
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH** इसमें बीस प्रश्न हैं हिन्दी और अंग्रेजी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Discuss the role played by the Directorate of Enforcement in the investigation of offence of money laundering and violations of foreign exchange laws. (Answer in 150 words)

10

भारत में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना
1956 में विदेशी मुद्रा बाजार के प्रबंधन
व नियंत्रण हेतु की गयी थी।

प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका व अधिकार:-

- ①. निम्नलिखित कानूनों का क्रियान्वयन
करके सुनिश्चित करना -

↳ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
(1998)

↳ ~~PM~~ FEMA का क्रियान्वयन

↳ भ्रष्टाचार अपराधी शोधन अधिनियम
(2015)

- ②. मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा अर्जित सम्पत्ति
की जप्ती करना।

- (3). मुद्रा व्यापार संबंधी अपराधों पर
नियंत्रण लगाना।

- संगठित अपराधी पर रोकथाम के प्रयास।
- ~~क~~ राष्ट्र विरोधी NQO द्वारा विदेशी मुद्रा की ~~क्रिया~~ अनियमितता पर रोकथाम लगाना।

चिंताएँ:-

- ECIR को अपराधी के साथ साक्षात् न किया जाना।
↳ प्राकृतिक न्याय की अवहेलना (हालांकि न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया को उचित माना गया)
- अपराध सिद्धि में कमी (लगभग 5000 केस में से 23 का ही निपटारा)।

सुधार:-

- तकनीकी कौशल
- ~~अंतरा-संस्था~~ अंतरासंस्था तंत्र को बेहतर करना।

भारत के ~~वर्षा/2016~~ TAX/GDP अनुपात में वृद्धि हेतु ED की कार्यक्षमता को और बेहतर करने की आवश्यकता है।

2. भारतीय संविधान भारत में उदार लोकतंत्र के विकास हेतु एक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है।
विश्लेषण कीजिए।

The Indian Constitution has been successful in providing a framework for liberal democracy to flourish in India. Analyse. (Answer in 150 words) 10

उदार लोकतंत्र से आशय एक ऐसी
शासन प्रणाली से है जो अधिकारों पर
केंद्रित हो, नागरिकों के मूल अधिकारों
को महत्व दिया जाता हो ताकि मानव का
सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय संविधान में उदार लोकतंत्र के तत्व :-

- प्रस्तावना - में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक
भुरसा पर बल,
न्याय, बंधुत्व इत्यादि को समाहित करना।
- मूल अधिकारों में व्यक्ति की अखण्डता
की स्वतंत्रता (Art 14); जीवन का अधिकार
[Art (21)], शिक्षा का अधिकार (Art 24)
- धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा (Art 25)
- कल्पसंरक्षणों की सुरक्षा (Art 26-28)

- राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा
उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना का
नैतिक दायित्व । (अनु 43 B(b))

अनु 39A → मुक्त विधिक सहायता ।

- न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार का
विस्तार । (पुट्टास्वामी वाद → निजता का
अधिकार)
- नवतेज जाँहर वाद (लैंगिक समानता का
अधिकार)
- पिशाखागाइलाइन काफ़ी ।

इस प्रकार भारत में संविधान
में उदारवादी दृष्टि के माध्यम से
भारत में मानव के सम्पूर्ण विकास की
लक्ष्य प्राप्ति पर बल दिया गया है।

3. "समनुषंगिता के सिद्धांत" से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना कीजिए।

What do you understand by the "principle of subsidiarity"? Discuss its importance in the context of India. (Answer in 150 words) 10

समनुषंगिता से आशय शक्तियों के हस्तांतरण से दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय शासन उच्चतम स्तर का कुशल शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्थानीय शासन को शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है।

भारत में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसी शक्ति सुनिश्चित की गयी है।

महत्व :-

- स्थानीय समस्याओं का बेहतर निपटारा।
- वन साइज किट माल समस्या का समाधान।
- स्थानीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा।

- सहभागिता लोकतंत्र की प्राप्ति।
- धन का विकेंद्रीकरण
 - ↳ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।
- स्थानीय नेतृत्व का उभार।

पुनर्जागरण :

- जटिल नीकरशाही
 - ↳ लक्ष्य प्राप्ति में बाधक।
- राज्यों व केंद्र द्वारा शक्तियों को त्यागने में क्षमिकता।
- शिक्षा, जागरूकता का अभाव।
- तकनीकी संवर्धन में कमी।

शासन के कुशल क्रियापथ को सुनिश्चित कर गंभीर स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देकर गांधी जी के स्वराज की स्थापना के लक्ष्य का साकारित किया जा सकता है।

4. "मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों का दमन करना नहीं होगा, बल्कि लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति उसी रूप में जागरूक बनाकर एक लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करना है, जिस प्रकार से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं।" चर्चा कीजिए।

"The moral value of fundamental duties would not be to smother rights but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights". Discuss. (Answer in 150 words) 10

भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनु. 51(A) के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की स्थापना की गयी है।

मूल कर्तव्यों का महत्व :-

- नागरिकों को राज्य के प्रति नैतिक दायित्व सुनिश्चित करना।
- नागरिकों में राष्ट्र के प्रति उसके आदर्शों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
- कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करना।
(परिणामों के प्रति व्यक्ति को त्यागना)
↳ (अप्रतकल में पंच प्रणामों में से एक)

- वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देना।
 - ↳ भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में सहायक।
 - पर्यावरणीय जागरूकता, वन संरक्षण को बढ़ावा।
 - ↳ सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति।
 - साम्प्रदायिकता, का त्याग, सर्वधर्मसमभाव।
 - ↳ कानून व्यवस्था में सुधार
- राज्य द्वारा प्रशासन पर प्रभावी ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।

वस्तुतः देखा जाये तो अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति यदि अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन सुरक्षित करें तो उसके अधिकार स्वयं ही सुरक्षित हो जायेंगे।

5. क्या आपको लगता है कि कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित विधान का प्रयोग शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है? भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Do you think the exercise of delegated legislation by the executive goes against the principle of separation of powers? Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

प्रत्यायोजित विधान से माशाय है
शासन की दिव- प्रतिदिन की जरूरतों
को ध्यान में रखकर कार्यपालिका
द्वारा नियम निर्माण से है जिसे स्वयं
विधायिका द्वारा कार्यपालिका को हस्तांतरित
किया जाता है।

प्रत्यायोजित विधान के उदाहरण:-

- कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश का प्रयोग।
- कानूनों पर नियम बनाने की शक्ति

शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध:-

- कानून निर्माण का कार्य विधायिका का, कतः उसके कार्य में हस्तक्षेप।
- स्थापित कानूनों से बाहर जाकर नियमों का निर्माण जैसे विजिल मीडिया हेतु

गाइडलाइन, कुछ आलोचकों द्वारा IT Act 2000 के तहत नियंत्रण से आगे जाती हैं।

- अध्यादेशों की पुनर्स्थापना (वॉ ६
4(SC → संविधान के साथ धोखाधड़ी)
4 विधायिका के महत्व को कम करती हैं।

आवश्यकता क्यों ?

- विधायिका की कार्यवाही स्थायी नहीं।
- कार्यपालिका द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता
(कोविड महामारी)
- अध्यादेश व नियमों का बाद में विधायिका द्वारा पालन किया जाना।

इस प्रकार प्रत्याखेपित विधान
सिद्धांतों में सही है इसके प्रयोग
के सहभावना के साथ किया जाना
सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6. दोषपूर्ण गवर्नेंस के पीछे प्रमुख कारण एक ढर्रे में सोचने की आदत और एकाकी कार्य प्रणाली है। भारत में लोक सेवाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए।
A key factor behind poor governance is a system of thinking and working in silos. Discuss in the context of public services in India. (Answer in 150 words) 10

भारत को भ्रष्टाचार में 2047 तक
विकसित भारत के लक्ष्य को साकारित
करने के लिए गतिशील व प्रो-पिपल
गवर्नेंस मॉडल की आवश्यकता है।

वर्तमान गवर्नेंस मॉडल के दोष:-

- नौकरशाही का जड़त्व → निर्णय निर्धारण में देरी
- नवाचार में कमी व प्रोत्साहन में कमी।
- विभागों में समन्वय का अभाव
↳ सड़क निर्माण के बाद टेलीफोन तारों का विस्तार।
- ↳ कार्य का दोहराव → NHAI
↳ राज्य विभाग

- संसाधनों पर दोहरा नियंत्रण ।
↳ विमान पल्लव व रक्षा मंत्रालय के कुछ परियोजना में तालमेल की कमी ।
(पुणे एयरपोर्ट का वायु सेना द्वारा प्रयोग)
- प्रशासनों का दोहराव ।
↳ कृषि बीमा में केंद्र राज्य योजनाओं का दोहराव (तेलंगाना, अजमेर)

सुधार

- गति शक्ति परियोजना
- लोकसंघों के प्रशिक्षण में सुधार ।
- CPGRAMS
- शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर किया जाये ।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा ।
- केंद्र - राज्य संबंधों में बेहतरी के प्रयास ।
↳ निपमित्त केंद्र राज्य परिषद बँके

सहकारिता के साधन का प्रयोग कर भारत 'विकसित भारत' का निर्माण कर सकता है ।

7. असुरक्षित गर्भपात भारत में महिलाओं के प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान कीजिए और उपचारात्मक उपाय भी बताइए।

Unsafe abortions are a critical issue affecting the reproductive and maternal health of women in India. Identify the reasons behind the same and suggest remedial measures as well. (Answer in 150 words) 10

भारत में असुरक्षित गर्भपात
मातृत्व मृत्यु दर को बढ़ाता है भारत
में महिलाओं की मृत्यु का छठवां प्रमुख
कारण असुरक्षित गर्भपात है। (NFHS-5)

उत्तरदायी कारक :-

- गर्भपात को लेकर सामाजिक धारणा
4 फलतः गैर - पंजीकृत गर्भपात में
बढ़ोत्तरी जो कि जोखिमपूर्ण होते हैं।
- महिलाओं के में यौन व प्रजनन स्वास्थ्य
शिक्षा स्तर में कमी (साक्षरता दर 68%)
(निका)
- सहमति पूर्ण यौन संबंधों का भी
पाश्चो चायन के तहत अपराध माना
जाना श्री असुरक्षित गर्भपात को बढ़ावा
देता है।

- पुत्र प्राप्ति की इच्छा (आर्थिक सर्वे)
4 इसके चलते महिलाओं की इच्छा
विद्वद् समाजिक पारिवारिक दबाव के
कारण गर्भपात को बढ़ावा।
- प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी (NPHS-5)

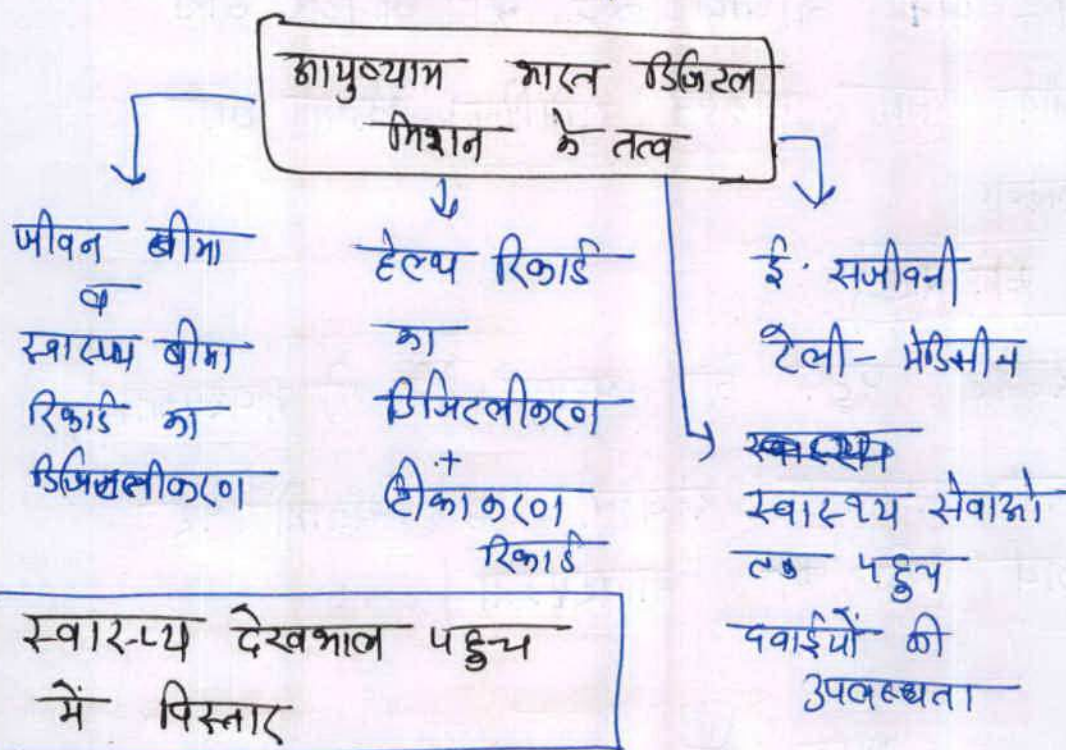
उपचारात्मक उपाय:-

- चिकित्सकों की शिक्षा स्तर में सुधार।
- महिलाओं SRM के प्रति जागरूकता
को बढ़ावा।
- जमीनी स्तर पर विज्ञापन, कैपेन का
आयोजन (नुम्बड नाटक)
- सुरक्षित गर्भनिरोधक उपायों तक पहुँच।
- पाक्सो अधिनियम में सुधार (SC का मत)

हालांकि हमें सुरक्षित गर्भपात की
समय सीमा को 24 सप्ताह किया
जाना असुरक्षित गर्भपात को कम करने व
महिलाओं के स्वयं के इशारे के प्रति अधिकारों
का मान्यता देने के संदर्भ में एक सार्थक कदम है।

8. डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और उसकी बहनीयता से संबंधित स्थायी मुद्दों का समाधान करने में सक्षम है। इस संदर्भ में, देश को 'डिजिटल स्वास्थ्य' क्रांति के मुहाने पर लाने में Ayushman Bharat Digital Mission की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Digital healthcare has the potential to address the perennial issues pertaining to accessibility and affordability of healthcare in India. In this context, discuss the role of Ayushman Bharat Digital Mission in putting the country at the cusp of a 'digital health' revolution. (Answer in 150 words) 10

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा
भारत में सतत विकास लक्ष्य-3
की प्राप्ति संभव है।



- इसके माध्यम से सुदूर पूर्व तक पहुंच बेहतर होगी।
- ~~स्वास्थ्य~~ टीकाकरण कार्यक्रम में सुधार।

- आजीवन स्तर पर सेवाओं की पहुँच से OOPF में कमी आएगी।

◦ वहनीयता :- ◦ लागत उभावी होने के चलते अधिक उच्चत • फलतः अन्य क्षेत्रों में खर्च की क्षमता में सुधार।

- आजीवन - शहरी विभाजन का काम करता है।
- PM - जन औषधि केंद्र की जानकारी द्वारा वहनीय दवा विकल्प सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ऊर्जा की शह :-

- इंटरनेट पहुँच को बढ़ावा देने की आवश्यकता।
- उदा. सैरक्षण संबंधी • चिंतनों पर कार्य करने की आवश्यकता।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभों का

कुशलतापूर्वक उपयोग अभी संभव होगा जब 'स्वस्थ भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी। अतः उपरोक्त चिंतनों पर कार्य करना आवश्यक है।

9. दक्षिण एशिया से एकमात्र G20 सदस्य के रूप में, भारत के लिए G20 का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया की आवाज को बुलंद करने के लिए एक प्रभावी मंच के तौर पर इस समूह का उपयोग करने हेतु एक आदर्श अवसर है। टिप्पणी कीजिए।

As the only G20 member from South Asia, the G20 leadership is an ideal opportunity for India to use it as an effective platform to amplify South Asia's voice at the global stage. Comment. (Answer in 150 words) 10

G20 की स्थापना 1999 में की गयी थी। यह मंच विश्व की 60% जनसंख्या, 70% वैश्विक व्यापार व 85% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है।

G20 में भारतीय नेतृत्व - दक्षिण एशिया की आवाज के रूप में :-

- दक्षिण एशिया की पर्यावरणीय समस्याओं को उठाया जा सकता है।
 - ↳ सर्वाधिक चकवात प्रभावित क्षेत्र।
 - ↳ CDDP पर ध्यान केंद्रित करा सकता है।
 - ↳ विकसित राष्ट्रों का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व।
- स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिकी तक पहुंच।
 - ↳ सहज भाषा की जरूरतों की पूर्ति।

हेतु वगलदेश, ~~का~~ इंडोनेशिया, भारत
थाईलैण्ड आदि को स्वच्छ जीवोमिक्की
की आवश्यकता।

- श्रॉतकवाद, मंनीलाईज पर कार्य
 - ↳ भारत द्वारा NMFT समिट की
बैंक
- सार्वधिक क्षेत्र में पुननिमिग की आवश्यकता
 - ↳ वैश्विक महामारी के अर्थव्यवस्था पर
व्यापक प्रभाव फलतः विकासशील
राष्ट्रो के लिए बाजार पट्टप में
सुधार।

भारत द्वारा G-20 बैंक से
पूर्व दक्षिण एशिया समिट, व NMCA
समिट उसकी उ प्रापमिकता के उवाति है
इस क पर प्रभावी कार्य करके भारत
दक्षिणी विश्व की बेहतुव आवाज बनकर
उभर सकता है।

10. भारत-यू.ए.ई. CEPA दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा भारत को इस क्षेत्र में व्यापक पहुंच प्रदान करेगा। चर्चा कीजिए।
The India-UAE CEPA will serve as a catalyst to bolster economic ties between the two countries and give India greater access to the region.
Discuss. (Answer in 150 words) 10

भारत - यूएई CEPA भारत
यू.ए.ई की गतिशील सामरिक बटनीति
के दशति है।

भारत · UAE CEPA के लाभ :-

- भारत की ऊर्जा आवश्यकता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
- इसके माध्यम से चीनी बटनीति को प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा।
- भारतीय प्रेक्षक में सुधार (UPR का अंतराष्ट्रीयकरण)
- UAE को भारत में निवेश का अवसर प्राप्त होगा।

भारत को व्यापक पहुँच:-

- चीन द्वारा अरब-ईरान समझौते के उपास के चलते भारतीय पहुँच को बढ़ावा देने में UAE CAPA महत्वपूर्ण होगा।
- UAE से आर्थिक संबंध पश्चिम एशिया व यूरोप तक पहुँच के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
- भारतीय उद्योगों को UAE में निवेश का अवसर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सम्भकारी।
- भारतीय मानव संसाधन को रोजगार का विकल्प प्राप्त होगा।

पश्चिम एशिया के बदलती गतिशील श्रृं-राजनीति में भारत का UAE से संबंधों में सुधार, भारत की इस क्षेत्र में आर्थिक-सांघरिक पहुँच को बेहतर करेगा।

11. एक दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली, सुविचारित कानून की अनुपस्थिति और डोमेन विशेषज्ञता की कमी को भारतीय न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियों के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा कीजिए।
A dysfunctional criminal justice system, absence of well-considered legislation and need for domain expertise, are being seen as the new challenges for the Indian judiciary. Discuss. (Answer in 250 words) 15

भारत में न्यायपालिका में 4.5 cr से भी अधिक विवादों का होना भारत में न्याय तंत्र के आपराधिक न्याय प्रणाली की कमियों को उजागर करता है।

दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली :-

- पुलिस में पर ~~बुरा~~ लोक व्यवस्था व भ्रष्टाचार एक सच दायित्व।
- फोरेंसिक जांच तंत्र की खराब स्थिति।
- पुलिस पर भ्रष्टाचार।

सुविचारित कानूनों की अनुपस्थिति :-

- कानून निर्माण में लेजी न्यायपालिका विवाद को खड़ा देती है।
- न्यूनतम कानून निर्माण की उपस्थिति

- विशेषज्ञों की राय की अवहेलना।
- समग्र, समावेशी कानूनों की अनुपस्थिति।
- अद्यतन की समस्या (ऑपनिवेशिक कानूनों की उपस्थिति)

डोमेन विशेषज्ञता की कमी:-

- फोरेंसिक एक्सपर्ट की कमी।
- न्यायपालिका में रिक्तियों।
- दृष्टान्त में तकनीकी सदस्यों की कमी।

सुधार के प्रयास :-

①. अपराधिक न्याय प्रणाली

- ↳ नवीन फोरेंसिक नीति
- ↳ अपराधियों के डाटा एकत्रित हेतु नया कानून।
 - ↳ बायोमेट्रिक डाटा संग्रहण
 - ↳ अपराध दोष सिद्धि में सुधार होगा।
- पुलिस रिफार्म - मॉडल एक्ट

- नवीन जेल सुधार अधिनियम
- नैट ग्रिड,
- CCTNS की स्थापना

कार्बन निमो → मॉडल राज्यों के
माध्यम से राज्यों को सुधार
सुझाव।

डोमेन विशेषज्ञता :- ० नये क्षेत्र यथा
हार्ड नेट, क्रिप्टोबाजार हेतु विशेषज्ञों
की नियुक्ति।

- अधिकारियों की मिड र्म टैमिंग
में सुधार।

भारत में ज्यादातर तंत्रों
समग्र सुधार हेतु शासन के तीनों अंगों
में समन्वय को बढ़ावा देकर नागरिक
समाज के सुझावों पर कार्य करने
की आवश्यकता है।

12. दल-बदल विरोधी कानून भारत में राजनीतिक अस्थिरता के मुद्दे को किस हद तक हल करने में सक्षम रहा है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

To what extent has the anti-defection law been able to address the issue of political instability in India? Discuss with suitable arguments. (Answer in 250 words)

15

भारत में 52 वे संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल अधिनियम अधिनियम की स्थापना की गयी है।

दल-बदल कानून की विशेषता :-

- इसके माध्यम से राजनीतिक दलों के विधायक/संसद के दलबदल को रोक रखा गया।
- दल के विषय के उल्लंघन पर सदस्यता खाने के प्रावधान।
- स्वतंत्र सदस्य के किसी भी पार्टी में शामिल होने पर प्रतिबंध।
- सरकार की स्थिरता को सुनिश्चित करने का प्रयास।

काबून के लाभ :-

- सरकारों की स्थिरता में सुधार हुआ।
- राजनीतिक सुचिता में सुधार।
- राजनीतिक संकट में कमी।
- चुनावों की बारम्बारता में कमी।
- सरकार द्वारा राजनीतिक घोषणापत्र पर कार्य आसान हुआ।
- विधायिका में काबून मित्रि बंस्तर हुआ।

काबून की कमियाँ :-

- सांख्यिक दलबल शोके में विकल।
(महाराष्ट्र, म.प्र. की बरनाए)
- ~~सं~~ स्पीकर द्वारा राजनीतिक इनग्रिड से मिगमि
- सौंसद / विधायिका की शक्तिव्यक्ति पर संकुश।
- प्रतिमिधि की क्षेत्र की अपेक्षा राजनीतिक दल के प्रति विच्छा।
- ~~क~~ असहमति पकटीकरण में कमी

- लोकतांत्रिक विचारों के विरुद्ध।

सुधार के प्रयास:

- दलबदल के सम्बन्ध में निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल द्वारा लिये जाये। (दिनेश गौस्वामी समिति)
- दलबदल पर समय सीमा (सामान्यतः 3 माह के भीतर निर्णय लिया जाये ताकि न्यायपालिका हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो। (मणिपुर MLAs द्वारा SC के आदेश पर हटाया गया)
- स्पीकर द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को व्याख्या अनिवार्य बनाया जाये।

दलबदल की घटनाएँ न केवल राजनीतिक संकट का कारण बनती हैं बल्कि यह नागरिकों में चुनावों के प्रति उत्साह को भी कम करती हैं अतः आवश्यक है कि उपरोक्त सुझावों पर कार्य किया जाये।

13. भारत में अंतर्राज्यीय नदियों का प्रबंधन परस्पर विरोधी संघवाद के कारण विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। चर्चा कीजिए। साथ ही, उन तंत्रों को रेखांकित कीजिए जिनका उपयोग भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है।

Governance of inter-state rivers in India suffers from various issues due to conflictual federalism. Discuss. Also, highlight the mechanisms, which can be utilised to resolve inter-state river water disputes in India. (Answer in 250 words) 15

भारत में अंतर्राज्यीय नदियों का प्रबंधन
भारम्भ से ही राजनीतिक, प्रशासनिक
संकट का कारण रहा है।

अंतर्राज्यीय नदी प्रबंधन तंत्र :-

- जल राज्य सूची का विषय किंतु प्रबंधन पर केंद्र की भी जिम्मेदारी।
- जल विवाद समाधान हेतु परिषदों का गठन (अनु 262)
- न्यायालय का हस्तक्षेप → (आ 131)
↳ (आ 136)
- अंतर्राज्यीय परिषदों के प्रस्ताव
- राज्यों के मध्य समझौते (केरल व तमिलनाडु)

विवाद के प्रमुख कारण :-

- क्षेत्रीय दलों द्वारा वोट बैंक राजनीति।
- क्षेत्रीय आकांक्षाओं को उभार देकर क्षेत्रवादी राजनीति।
- जल संसाधन का असुल पबंधन।
- जलवायु परिवर्तन।
- सदावाही नदियों में कमी (प्रायद्वीपीय भाग)
- राजनीतिक शूछावाक्ति में कमी।
- न्यायिक अतिरेक।

समाधान के प्रयास :-

- नदी जल विवादों पर बने न्यायिक अद्विगणों का सम्मेलन।
- जल दक्षता में सुधार के प्रयास
नीति आयोग → (रिम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट कन्सेप्स)
- वेस्टर जल ~~का~~ बारबारा लेन
↳ वैज्ञानिक पद्धति जिसमें आवश्यकता

पुनर्निर्माण, जल संरक्षण को महत्व
दिया जाये।

- जल संभार क्षेत्रों का विकास।
- वर्षा जल संरक्षण।
- अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में मुद्दों का
प्रयास।

वस्तुतः जल एक प्रभावी
संसाधन है जिसका संरक्षण का
प्रयास विवाद समाधान का प्रमुख
रूप होना चाहिए जो वही
समाधान है। राष्ट्रीय दिन को
क्षेत्रीय स्तर पर अधिकृत देना भी
आवश्यक है।

14. उत्तर-औपनिवेशिक दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय संविधान के उन मूलभूत पहलुओं का सविस्तार वर्णन कीजिए, जिनके संदर्भ में यह अपने समकालीन संविधानों से भिन्न था।

Elaborate on the fundamental aspects in which the Indian Constitution differed from its contemporaries despite being a post-colonial document.

(Answer in 250 words)

15

भारतीय संविधान पर सदैव यह आक्षेप लगाया जाता रहा है कि यह उच्चार का संविधान है।

किंतु इसके प्रति उत्तर में बी. आर. अम्बेडकर का कथन महत्वपूर्ण है जहाँ उन्होंने कहा कि "भारतीय संविधान के निर्माण के समय कई संविधानों का अध्ययन पर भारतीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है।"

समकालीन संविधान का उभावः

ब्रिटेन → संसदीय शासन प्रणाली
→ संसद के प्रति कार्यपालिका
अंतर्दायित्व

USA → मूल अधिकारों का प्रावधान
→ उपराज्यपति का पद

फ्रांस → स्वतंत्रता समानता वैयुत्व

ऑस्ट्रेलिया → संयुक्त बैंक का
प्रवधान

जर्मनी (वाइमर गणतंत्र)

↓ आपत्कालीन प्रवधान

समकालीन संविधानों से शिन्ता है-

- ब्रिटेन के समान शोडो कैबिनेट नहीं होना।
- ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की अपेक्षा भारत में गणतंत्र का आपनाना।
(सभी पद नागरिकों को उपलब्ध)
- संसदीय सर्वोच्चता की अपेक्षा संविधान की सर्वोच्चता।
- अमेरिकी श्रलक्षधिकारों में सम्पत्ति व हरिशा रखना श्रलक्षधिकार किंहु भारत में अनुपस्थिति।

- अमेरिका में अध्यक्षीय शासन भारत में संसदीय शासन (मूल ढाँचे में शामिल)
- फ्रांस के समान राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं।
- आस्ट्रेलिया की भाँति जजों की नियुक्ति के हेतु न्यायिक आयोग नहीं (भारत में कालेजियल प्रणाली)
- अमेरिका में न्यायिक नियुक्ति में राष्ट्रपति व सीनेट की भूमिका (भारत में अनुपस्थिति)

इस प्रकार भारतीय संविधान, संविधानमित्रताओं की इरवर्धी, विवेकपूर्ण समझ, लोकतंत्र में आस्था का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।

15. मुफ्त उपहार, विशेष रूप से चुनावों से पहले, समाज के लिए लाभकारी होने की बजाय अधिक हानिकारक हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में युक्तिसंगत तर्क दीजिए।

Freebies, especially ahead of elections, do more harm than good to the society. Do you agree? Give logical arguments in support of your answer.
(Answer in 250 words) 15

मुफ्त उपहार को सरकारों द्वारा
• अपने नागरिकों को बिना शर्त
सेवा व वस्तु की उपलब्धता
सुनिश्चित करके कराने के रूप में
समझा जा सकता है।

मुफ्त उपहार के समाज पर नकारात्मक
प्रभाव :-

- समाज में नवगण, कौशल को प्रभावित करता है।
- व्यक्ति के मत को मुद्रा में झुकाव जनमत के महत्व को कम करता है।
- मध्यमवर्गीय उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा। (जैसे बिजली के चलेने दिल्ली में AC, माइक्रोवेव आदि वीखपत में वृद्धि)

- पर्यावरण संरक्षण के विपरीत।
4 फ्री बिजली ऊतः जल का दोहन
(सिंचाई हेतु → पंजाब)
वाटर टेबल का नीचे जाना)
- गांधी के सात पापों में शामिल
(बिना श्रम ~~धन~~ धनोपाज्जीन)

सरकार पर प्रभाव

- वारम्बारता में ह्रास।
- राजकोषीय स्थिति पर प्रभाव
(पंजाब का कर / GDP अनुपात)
47% तक
राजस्थान 35% जब
केंद्रीय सहायता पर निर्भरता को बढ़ावा।
- राज्य में विकास कार्य पर संकट।
(कनारिक का उदाहरण)
- अन्य सामाजिक कार्य पर प्रभाव।
(शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि पर कम निवेश)

आगे की राह:-

- सकारात्मक परिणाम देने वाली योजना जैसे ICDS, MDM को बनाये रखा जाये (~~सब~~ स्टैरिंग में 32% की रमी NFHS-5)
- महिला केंद्रित योजनाएं जैसे मुक्त परिवार द्वारा महिला सुरक्षा में सुधार हुआ है।
- घोषणा के समय विलेन प्रबंधन प्रस्ताव को भी नागरिकों के समक्ष रखा जाये।
- मतदाता जागरूकता कार्यक्रम।

मुक्त उपहार की पारम्परता व विस्तार स्वयं राजनीतिक दलों की स्तर

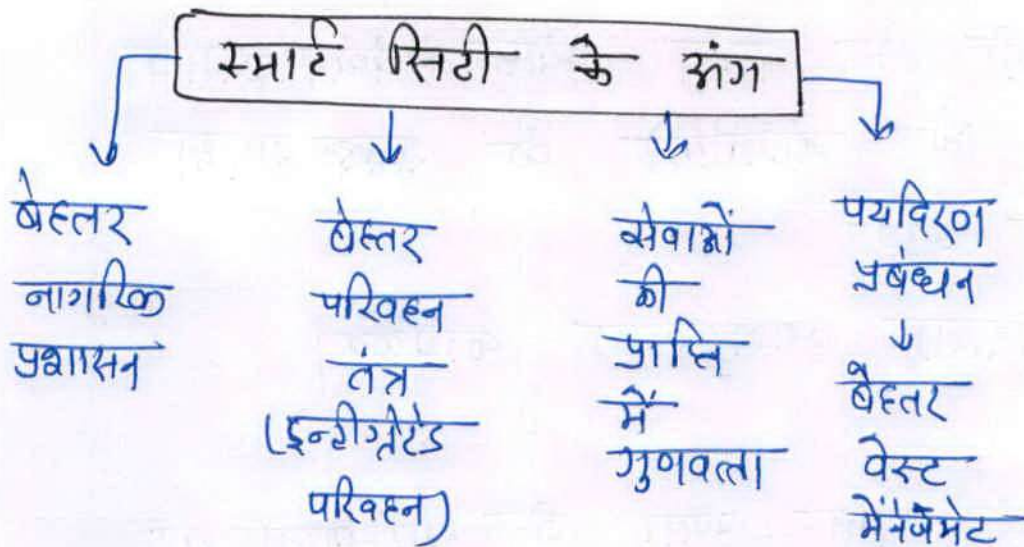
को प्रचलित बाद चुनौती बन सकता है।

नोट: इस संवेद्य में विवेकशीलता व तार्किकता को बढ़ावा देकर ही कोई घोषणा की जानी चाहिए।

16. भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस मिशन को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

The Smart Cities Mission, which was launched to change the urban landscape of India has produced mixed results. Discuss. Also, highlight the challenges faced in executing the Mission. (Answer in 250 words) 15

भारत में 2015 में सतत विकास लक्ष्यों की बेस्तर प्राप्ति हेतु स्मार्ट सिटी योजना शुरु की गयी।



स्मार्ट सिटी मिशन के परिणाम :-

सकारात्मक :-

- नागरिक प्रशासन डिजिटलीकरण में सुविधा
- वित्त प्राप्ति में सुधार।

- ₹ 80% कामरेम अपनी समयसीमा में पूरे।
- पर्यवेण सुझा में बेस्तर मॉडल कि विकास।

इंटीर

↗

↘

↓

स्वच्छता
 बायो गैस मॉडल
 परिवहन में प्रयोग
 (i-Bus)
- सेवा शक्ति में सुधार
(पैगलॉर मॉडल)
- नेकारालक :-
- पूर्वी भारत में परियोजना सिगि गति कमी
- संस्थाओं को दोहराव (SPV व शहरी प्रशासन)
- तासगेल की कमी।
- पित्त पर SPV द्वारा नियंत्रण)
- विकेदीकरण की कमी।

सुधार के बिन्दु:-

- शहरी प्रशासन तंत्र का क्षमता निर्माण।
- SPV व शहरी प्रशासन समन्वय में सुधार।
- वित्त हेतु निश्चिता में कमी को दूर करने हेतु इसका दायित्व
- शहरी स्थानीय प्रशासन को दिया जाये।
- SPV द्वारा केवल संबंधीय श्रमिका निभायी जाये।

स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा स्थापित जिला केंद्रीय सूचना केन्द्र में कोविड महामारी में उच्च श्रमिका निभायी तो 2050 तक लगभग भारत की 50% आबादी शहरों में निकल करेगी अतः शहरों को संघायीय बनाने के व्यापक प्रयास आवश्यक हैं।

17. यह तर्क दिया गया है कि भारत में उद्यमिता परिवेश के समक्ष विद्यमान विभिन्न बाधाओं के बावजूद, भारत के भविष्य को इसके उद्यमियों द्वारा आकार दिए जाने की संभावना है। टिप्पणी कीजिए।
It has been argued that despite several hurdles faced by the entrepreneurship ecosystem in India, the future of India is likely to be shaped by its entrepreneurs. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारत विश्व में एक स्टार्ट अप
इकोसिस्टम का एक हब बनकर
उभर रहा है वर्तमान में भारत
में 100 से अधिक मुनिकानी
स्टार्टअप की उपस्थिति इसका प्रमाण
है।

संभावना के बावजूद कुछ
समस्याएँ इसके विकास को बाधित
करती हैं जैसे:-

विद्यमान बाधाएँ:-

- आर्थिक संजी प्राप्ति के कम साधन।
(FDI नियमों की जटिलता)
- नालकिताशायी (सरकारी उद्यमों के
बावजूद भंगी भी करती)
- सामाजिक परिप्रेक्ष्य जहाँ स्वामीशेजगार
को महत्व दिया जाता है नवाचार

को कम जोत्साहन।

- RLD में कमी (GDP का 0.6% वही चीज में 2.1%)
- विनियामकीय जटिलताएं।
- केंद्र-राज्य संबंध (उद्योगों के विस्तार को चुनौती Foxconn द्वारा निवेश वापस लिया जाना)

संभावनाएं :-

- स्टार्टअप ईकानामी में नवाचार को बढ़ावा देने के साथ रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं।
- सरकार के सहयोगी की भूमिका।
 - शिक्षा → डिजिटल शिक्षा
 - डिजीवरी तंत्र → राशन तक पहुंच
 - इ. मेडिसीन → स्वास्थ्य सुविधा
- स्टार्टअप परिवेश में लैंगिक समानता का तत्त्व विद्यमान (40% स्टार्टअप की फाउंडर महिलाएं)

सुधार के प्रयास -

- विनियामकीय सुधार ।
↳ वित्त तक पहुँच सुविधाजनक ।
- मजदूरी तंत्र में सुधार ।
↳ सिंगल विट्रो क्लीयरेंस ।
- सहयोग को बढ़ावा ।
↳ करो' में बूटा
- Tier - 2 व 3 शहरों में विस्तार
को प्रोत्साहन (PLI योजना)

~~भारत को 5 ट्रिलियन~~ भारत को 5 ट्रिलियन
डॉलर आयव्यवस्था व हरीप बढ़ी
आयव्यवस्था बनाने में स्टार्टअप
इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु
उपरोक्त सुधारों पर कार्य ~~करना~~
करना आवश्यक है ताकि अनसुलझीप
लाभांश का बेहतर प्रयोग किया
जा सके ।

18. हालांकि, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना ने लैंगिक भेदभाव पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन यह खराब कार्यान्वयन और निगरानी के कारण वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही है। चर्चा कीजिए।

Though the 'Beti Bachao, Beti Padhao' scheme has given much-needed attention to gender discrimination, it has failed to yield desired results due to poor implementation and monitoring. Discuss. (Answer in 250 words) 15

समाज के व्यवहार परिवर्तन हेतु
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की
शुरुआत हरियाणा के हिसार से
की गयी थी।

योजना के मुख्य लक्ष्य:-

- कन्या श्रृंगार पर उन्नावी विधेयन
लगाया जाये।
- कन्या बाल विवाह को रोकने के
उपाय।
- कन्या शिक्षा का बढ़ावा।
- कन्या के शारीरिक स्वास्थ्य में
सुधार के उपाय।
- समाज में जागरूकता।

पुश्चाव :-

- सामाजिक धारणा में बदलाव।
- सकल नामंकन में सुधार।
- बालविवाह में कमी (NPHS-5)
- IMR, MMR में कमी।

कमियाँ :-

- योजना का 80% व्यय विज्ञापन (मुख्यतः डिजिटल व TV) पर) में खर्च किया जाना।
- अभी भी सकल नामोक्तन में अंतर।
- स्वास्थ्य पर आपेक्षित परिणामों में कमी (एनीमिया की स्थिति)

सुधार के बिंदु :-

- विज्ञापन रणनीति में बदलाव।
 - ↳ नुककड़ नाटको, रेडियो व स्थानीय भाषा का उपयोग

- निर्भया फंड व अन्य ~~सुझ~~ योजनाओं का अग्रेसर।
- PCPNDT Act का ~~कठोर~~ प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाये।
- शैक्षणिक सहायता पर ध्यान देते हुए शाला शिक्षा के साथ उच्चतर शिक्षा में नामंकन को बढ़ावा (STEM शिक्षा का विस्तार)

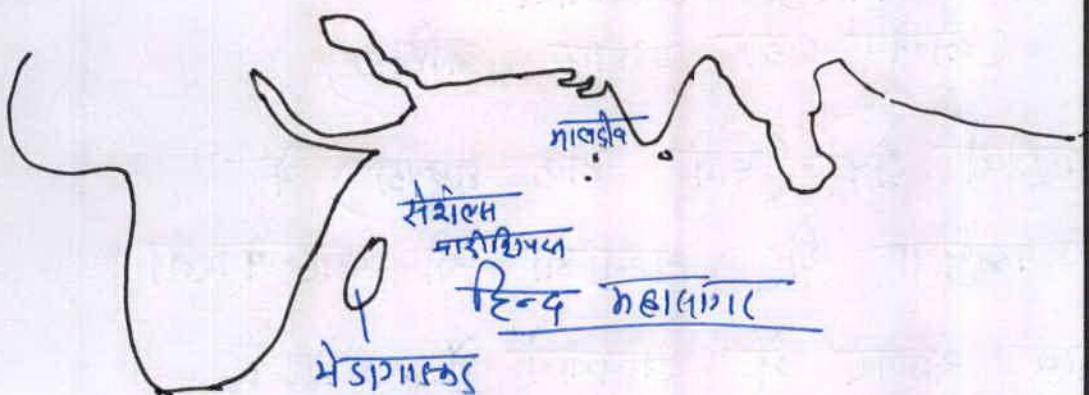
अभूतकाल के पंच प्रण में महिला विरोधी मानसिकता का त्याग, भारत को 2047 तक आधुनिक राष्ट्र बनाने में सहायक होगी। इसी प्रकार 49% परिवेशित आबादी का विकास करके ही भारत ~~का~~ समावेशी भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

19. दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा खतरों के स्वरूप और उनकी बारंबारता में वृद्धि के मद्देनजर, इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के संबंध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

As security threats increase in form and frequency in the South-West Indian Ocean, discuss the role played by India in relation to small island developing states (SIDS) in the region. (Answer in 250 words) 15

हिंद महासागर में भारत की
उपस्थिति एक वृद्ध स्थिर युद्ध पौत
के समान है जो इसे क्षेत्र में
भारत ने सुरक्षा प्रदाता
की

हिंद महासागर में भारत की
उपस्थिति इसे क्षेत्र का नेट सुरक्षा
प्रदाता के रूप में स्थापित करती
है।



लघु द्वीपीय देशों की हिंद महासागर में भारत की जिम्मेदारियों को बढ़ाती है।
हिन्द महासागर में मालदीव सेबोल्स, मारीशियस, काँफे SIDS उपस्थित हैं।

SIDS पर सुरक्षा खतरें :-

- अस्तित्व पर संकट।
 - ↳ जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभाव
 - ↳ अजलमग्नता (मालदीव)
- कनेक्टिविटी में बाधा।
- अर्थव्यवस्था का संकुचित आधार।
 - ↳ पर्यटन, मत्स्यपालन (कोविड का प्रभाव अधिक)
- सूफ्रीकी क्षेत्र (हार्न आफ अफ्रीका) में जलदस्तुता की घटनाओं की बारम्बारता।
- गरम सागर में तापमान में वृद्धि।
 - ↳ चक्रवात की बारम्बारता में वृद्धि

- जल के तापमान में वृद्धि
4 मत्स्यपालन प्रभावित।
- चीनी विदेशी नीति।
↳ दक्षिण जल नीति (मालदीव)

भारत के प्रयास

- HADR सहायता
- CRDI के तहत आपदा प्रबंधन
संवर्धन व मिमि में सहायता
(मैलागास्कर, मालदीव)
- I O P I की स्थापना।
- फ्रांस-भारत का हिन्द महासागरीय द्वीपीय
राष्ट्रों के विकास में सहायता।
- नौसेना द्वारा अरब सागर में जलदूषण
घटना पर जांच शुरू लगाया गया है।

वस्तुतः ये द्वीपीय राष्ट्रीय SIDS
भारत को पृथक् आर्थिक लाभ उपान
कर सकते हैं (जैसे EEZ) साथ ही
UN में इनका सहयोग भारतीय प्रस्तावों
की सफलता को सुनिश्चित करेगा।

20. चूंकि भारत अपने पड़ोस की पुनः कल्पना कर रहा है, इसलिए उप-क्षेत्रों के माध्यम से सीमा-पार कनेक्टिविटी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। विश्लेषण कीजिए।
As India re-imagines its neighbourhood, cross-border connectivity through sub-regions is becoming increasingly vital. Analyse. (Answer in 250 words)15

भारत की दक्षिण एशिया में विदेशनीति का प्रमुख बल पड़ोसी प्रथम व पूर्वी की ओर देखों नीति रही है।

इस संदर्भ में भारत अपने निकट के देशों में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लक्षित कर रहा है।

सीमा-पार कनेक्टिविटी के प्रयास:-

- BIMSTEC देशों से सहयोग
 - ↳ IMA हार्बो निमग्न पर ध्यान
 - ↳ BBIN कारिडोर पर कार्य।
 - ↳ कलाफान मल्टी मोडल परियोजना।
- INSTC परियोजना द्वारा पश्चिमी ~~क्षेत्र~~ पड़ोसियों से जुड़ाव के प्रयास

- पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न ~~समस्या~~ समस्या को विफल करने हेतु चाबहार परियोजना पर कार्य ताकि ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुँच बनायी जा सके।
- मालदीव में चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना का विकास।
- श्रीलंका में कोलम्बो पोर्ट परियोजना (वेस्टन) [जापान की सहायता द्वारा]

पुनर्निर्माण:-

- घोषणा व क्रियान्वयन में काल।
- क्षेत्रीय राजनीति में बार-बार परिवर्तन (नेपाल श्रीलंका)
- कुछ परियोजनाओं में देरी।
(ISIN व INAT)
- अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट
- वित्त की कमी।

समाधान के प्रयास:-

- क्षेत्रीय गठबंधनों के माध्यम से समस्या समाधान का प्रयास
(BIMSTEC - X रणनीति)
- सागर ड्राफ्टिंग के माध्यम से हिंदी पड़ोसी राज्यों की सहायता (HADR)
(वैकसीन मंत्री)
- ~~इस~~ गुजरात ड्राफ्टिंग का उभावी प्रयोग।

भारत को वैश्व शक्ति बनने का मार्ग दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शक्ति को मजबूती ~~बनाकर~~ बनाये रखने से होकर गुजरता है फलतः इन परिघोषनाओं का सफल क्रियोवधन भारतीय विदेशनीति की सफलता के लिए आवश्यक है।